प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी जयपुर–अजमेर
दिनांकः 08.04.2026
समय : 01:00 पी.एम.

भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसे पांच दशमलव दो–पांच प्रतिशत पर यथावत रखा गया है। आज मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई के गर्वनर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने तटस्थ रुख अपनाते हुए सर्वसम्मति से रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया है। गवर्नर की अध्यक्षता में समिति की बैठक सोमवार से शुरू हुई थी। मौद्रिक नीति समिति ने पिछले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद–जीडीपी सात दशलमव छह प्रतिशत और चालू वित्त वर्ष के लिए 6 दशलमव 9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि ऊर्जा की कीमतों में हाल ही में हुई बढोतरी से महंगाई बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 4 दशमलव 6 फीसदी रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं पर लगातार नजर रखे जाने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 11 साल पूरे हो गए है। 2015 में शुरू हुई ये योजना युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के लगभग 58 करोड़ ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से दो–तिहाई ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। लगभग 12 करोड़ युवाओं को इस पहल से लाभ हुआ है। इस योजना में लघु व्यवसायों को समर्थन देने के लिए 20 लाख रुपये तक के सरल, आसान और बिना गारंटी वाले ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। मुद्रा ऋण चार श्रेणियों में दिए जा रहे हैं, जिनमें शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि कि मुद्रा योजना से स्वरोजगार को बढावा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि जब लोगों को सही अवसर मिलते हैं, तो वे आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय कल से देशभर में पोषण पखवाड़ा के 8वें संस्करण का आयोजन करेगा। पोषण के महत्व पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा है कि एक स्वस्थ बच्चा ही मजबूत राष्ट्र की नींव है। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि हर मां और बच्चे के लिए संपूर्ण पोषण सुनिश्चित करने का जन आंदोलन है। पोषण पखवाड़े का विषय– thou d igy Ng o"k e efLr"d dk vf¶kdre fodkl रखा गया है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि प्रारंभिक बचपन, विशेष रूप से पहले एक हजार दिन, दिमागी और शारीरिक विकास तथा समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। पखवाड़े के दौरान, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां होंगी। इनमें माताएं, देखभालकर्ता, परिवार, सामुदायिक संस्थाएं और स्थानीय निकाय भाग लेंगे। इस दौरान पोषण पंचायतें, जागरूकता सत्र, प्रारंभिक प्रोत्साहन गतिविधियां, खेल आधारित शिक्षण पहल और छोटे बच्चों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने तथा स्क्रीन टाइम कम करने के अभियान होंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बूंदी दौरे पर है। श्री शर्मा जिले के इंदरगढ तहसील के गुहाटा गांव पंहुचे है। मुख्यमंत्री यहां राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत किये जा रहे चम्बल एक्वाडक्ट निर्माण कार्यो का जायजा ले रहे है। गौरतलब है कि चम्बल एक्वाडक्ट, रामजल सेतु लिंक परियोजना–संशोधित पीकेसी का महत्वपूर्ण घटक है जो कोटा के पीपलदा समेल गांव से बूंदी के गुहाटा गांव तक बनाई जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री का करौली जाने का कार्यक्रम है। वे नांगल

शेरपुर में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री शर्मा देर शाम पुष्कर में एक धार्मिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

प्रदेश में बढते साईबर अपराधों को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने आम लोगों से सतर्क रहने और डिजिटल माध्यमों का सही उपयोग करने की अपील की है। साइबर क्राइम उप महानिरीक्षक शांतनू कुमार सिंह ने बताया कि साइबर धोखाधडी पर रोक के लिए दूरसंचार विभाग के संचार साथी एप के तहत चक्षु पोर्टल बनाया गया है। ये पोर्टल धोखाधडी में इस्तेमाल किये गये मोबाईल नम्बर को बंद करने के साथ–साथ उसे ब्लेकलिस्ट कर देता है, जिससे साईबर अपराधी उस फोन में दूसरी सिम डालकर दोबारा ठगी नहीं कर पाते। श्री सिंह ने लोगों से साईबर धोखाधडी की शिकायत हैल्पलाईन नम्बर 1930 पर करने का आग्रह किया है।

संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल तक राज्यस्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। इन चार दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला से बाबासाहब के जीवन दर्शन और संविधान जागरूकता का संदेश जनजन तक पंहुचाया जायेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि इस दौरान फिल्मों का प्रदर्शन, ऑनलाईन क्विज, संविधान शपथ सहित कई कार्यक्रम होंगे।